Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 28 Oct, 2025

Edition : International

Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : Polity and Governance / Prelims	EC ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR 2.0 की शुरुआत की
Page 04 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	भारत ने गाजा शांति योजना का स्वागत किया, यूक्रेन युद्ध की शीघ्र समाप्ति की कामना की: जयशंकर
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science and Tech	स्टैनफोर्ड/एल्सेवियर की रैंकिंग सूची: हर चमकती चीज़ सोना क्यों नहीं होती
Page 08 Syllabus : GS 2 : Governance & Social Justice / Prelims	बड़ी टेक कंपनियों का भारतीय जन स्वास्थ्य के प्रति तिरस्कार
Page 10 Syllabus : GS 1 : Indian Society / Prelims	क्या भारत में डोगरी भाषा की लोकप्रियता कम हो रही है?

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page 08 : Editorial Analysis

उत्तर-दक्षिण कार्बन बाज़ार सहयोग की शुरुआत

Syllabus : GS 2 : International Relations

Page 01 : GS 2 : Polity and Governance

भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR 2.0) का दूसरा चरण शुरू किया है। यह अभियान 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलेगा, जिनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनावी राज्य शामिल हैं। इस प्रक्रिया के तहत 51 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची की सत्यापन, अद्यतन और मानकीकरण किया जाएगा।

हालांकि, असम को इस प्रक्रिया से फिलहाल बाहर रखा गया है क्योंकि वहाँ नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) और एनआरसी (NRC) से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अलग प्रक्रिया चल रही है।

EC kicks off SIR 2.0 in 12 States and U.T.s

EC says exercise will be held in poll-bound Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, and Puducherry

The commission says no SIR in Assam for now, because of separate provisions for citizenship

There is likely to be controversy in West Bengal and T.N. as ruling parties have raised concerns

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

The Election Commission on Monday kicked off the second phase of the special intensive revision of voter lists in 12 States and Union Territories, including in poll-bound Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, and Puducherry. The revision will cover 51 crore voters.

With the announcement of the second round, the voter lists of the States and Union Territories were set to be frozen from Monday midnight.

For now, there will be no SIR in Assam, scheduled to go to the polls next year, and a separate order will be issued later.

"Under the Citizenship Act, there are separate provisions for citizenship in Assam. Under the supervision of the Supreme Court, the exercise of checking citizenship is about to be completed. The June 24 SIR order was for the entire country. Under such circumstances, this would not have applied to Assam," Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said at press conference.

The exercise will be in focus in West Bengal and Tamil Nadu, where the ruling parties – the Trinamool Congress and DMK – have raised concerns. The SIR will be conducted in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Andaman and Nicobar Islands, and Lakshadweep.

Rolls revision

Phase 2 of the special intensive revision of electoral rolls will be held between November 2025 and February 2026 across 12 States and Union Territories, covering 51 crore voters

TIMELINE
- Enumeration start: November 4, 2025
- Enumeration end: December 4, 2025
- Draft electoral rolls release: December 9, 2025
- Final electoral rolls publication: February 7, 2026

The first phase of SIR was held in Bihar. FILE PHOTO

UNION TERRITORIES: Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Puducherry

STATES: Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, T.N., U.P., Bengal

DOCUMENT PROCESS
- No documents are to be collected from electors during the enumeration phase
- For electors who have not returned enumeration forms, the booth-level officer may identify a probable cause, such as death or duplication based on an enquiry from nearby electors and note the same
- These names will be displayed on boards of all panchayat and urban local body offices

EC modifies some rules based on Bihar lesson

NEW DELHI

Certain modifications have been made to the process based on the learnings from the just- concluded process in Bihar. In a notice issued to the Chief Electoral Officers of all 12 States and Union Territories, the EC said no documents were to be collected from electors during the enumeration phase. » PAGE 4

The first phase of the SIR was held in Bihar following which more than 68 lakh names were deleted from the electoral rolls.

Most States had the last SIR of the voter lists done between 2002 and 2004, and they have nearly completed the mapping of current electors according to the last exercise.

Voter mapping involves standardising addresses and correcting discrepancies.

In this phase of the SIR, the house-to-house enumeration will take place for a month from November 4 to December 4, and the draft rolls will be published on December 9.

Claims and objections can be raised from December 9 to January 8. Notices will be issued, and hearings and verifications will take place between December 9 and January 31. Booth-level officers will be trained, and forms will be printed between October 28 and November 3. The final electoral rolls will be published on February 7, the poll body said.

To a question on the demands for putting off the SIR exercise in Kerala where local body elections are scheduled, Mr. Kumar said the poll notification was yet to be issued.

On the SIR in West Bengal, where the ruling Trinamool Congress has raised concerns about the exercise, the CEC said the Commission was doing its constitutional duty by carrying out the SIR, and the State government will perform its duties by giving all support and manpower needed.

Asked whether the poll body will give new EPIC cards to all voters as stated during the SIR in Bihar, Mr. Kumar said fresh voter IDs will be given to only those who have any change in their particulars.

मुख्य विश्लेषण – UPSC Prelims के लिए (तथ्य आधारित बिंदु)

1. **SIR (Special Intensive Revision) क्या है?**

- यह निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाने वाला एक मतदाता सूची का विशेष सत्यापन अभियान है।
- इसमें घर-घर सर्वे, मृत या दोहराए गए नामों को हटाना, और पते की त्रुटियों का सुधार किया जाता है।

2. **SIR 2.0 का दायरा:**
   - यह 12 राज्यों/के.शा.प्र. में चलेगा – तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप।
   - कुल 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा।
3. **समय-सीमा:**
   - घर-घर सत्यापन: 4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025
   - ड्राफ्ट रोल प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
   - दावे और आपत्तियाँ: 9 दिसंबर – 8 जनवरी 2026
   - सुनवाई और सत्यापन: 9 दिसंबर – 31 जनवरी 2026
   - अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
4. **असम को बाहर क्यों रखा गया?**
   - असम में नागरिकता की अलग प्रक्रिया चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है।
   - इसलिए SIR 2.0 फिलहाल वहाँ लागू नहीं होगा।
5. **पहले चरण (SIR 1.0) का अनुभव:**
   - बिहार में हुआ था।
   - इसमें 68 लाख से अधिक नामों को मतदाता सूची से हटाया गया।
6. **नए मतदाता पहचान पत्र (EPICs):**
   - केवल उन्हीं मतदाताओं को नया कार्ड मिलेगा जिनके विवरण (details) में बदलाव हुआ है।

मुख्य विश्लेषण – Mains के लिए

1. **SIR 2.0 का उद्देश्य और महत्व:**
   - यह मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कदम है।
   - इससे डुप्लीकेट या अवैध प्रविष्टियाँ हटाकर चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत किया जाएगा।
2. **शासन और प्रशासनिक पहलू:**
   - यह निर्वाचन आयोग के संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 324) को दर्शाता है।
   - इसमें राज्य सरकारों, बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) और अन्य एजेंसियों का समन्वय जरूरी है।
3. **राजनीतिक संवेदनशीलता और विवाद:**
   - पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ruling पार्टियों ने प्रक्रिया पर चिंता जताई है।
   - असम में नागरिकता से जुड़े मुद्दों के कारण राजनीतिक विवाद की संभावना बनी हुई है।
4. **तकनीकी और प्रबंधन सुधार:**
   - Voter Mapping, Address Standardization और Digital Record Keeping पर जोर दिया जा रहा है।
   - इससे डाटा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
5. **चुनाव सुधारों में योगदान:**
   - SIR 2.0 से बोगस वोटिंग, मृत मतदाताओं के नाम, और डुप्लीकेट एंट्री को हटाने में मदद मिलेगी।
   - यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता के भरोसे को बढ़ाने वाला कदम है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- SIR 2.0 निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें सटीकता लाना है। असम को इसमें फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।
- यह पहल मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका को सशक्त बनाती है। हालांकि, इससे जुड़े राजनीतिक विवाद, नागरिकता संबंधी जटिलताएँ, और प्रशासनिक चुनौतियाँ इसकी संवेदनशीलता को भी दर्शाती हैं।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित में से कौन-से कथन "Special Intensive Revision (SIR)" से संबंधित सही हैं?

1. यह मतदाता सूची के सत्यापन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाने वाला अभियान है।

2. 2025 का SIR 2.0 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा।

3. असम को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहाँ नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अलग प्रावधान हैं।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1

(d) 1, 2 और 3

Ans : a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता मतदाता सूची की शुद्धता पर निर्भर करती है।इस कथन के प्रकाश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2.0) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

Page 04 : GS 2 : International Relations / Prelims

कुआलालंपुर में आयोजित 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों पर भारत की स्थिति दोहराई। उन्होंने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाज़ा शांति योजना का समर्थन किया और यूक्रेन युद्ध के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।

जयशंकर ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले ये संघर्ष वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, व्यापार में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और भू-राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाते हैं, जिससे ग्लोबल साउथ (भारत सहित) प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत लचीली सप्लाई चेन सुनिश्चित करने और आसियान देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है — विशेषकर "एक्ट ईस्ट नीति" और "इंडो-पैसिफिक विजन" के अंतर्गत।

Daily News Analysis

India welcomes Gaza peace plan, wishes for early end to Ukraine war: Jaishankar

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

India recognises that enduring conflicts have the potential to disrupt food security and threaten energy flows, and, therefore, it welcomes the Gaza peace initiative by U.S. President Donald Trump and wishes for an early end to the conflict in Ukraine, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Monday.

Speaking at the 20th East Asia Summit in Kuala Lumpur, Mr. Jaishankar spoke in favour of deepening maritime connections in the ASEAN region. "We are also witnessing conflicts that have significant repercussions, near and far. Deep human suffering apart, they undermine food security, threaten energy flows and disrupt trade. India, therefore, welcomes the Gaza peace plan. We also seek an early end to the conflict in Ukraine," he said.

Global stage: External Affairs Minister S. Jaishankar at the 20th East Asia Summit, in Kuala Lumpur on Monday. ANI

Earlier, Mr. Jaishankar met Secretary of State Marco Rubio as India-U.S. relations continue to remain uneasy after Mr. Trump imposed penalty tariffs on India for buying Russian crude.

Mr. Jaishankar, on his part, did not specifically refer to the challenges that India is facing because of Mr. Trump's campaign to cut down Russian energy exports but pointed at "reliability of supply chains and access to markets" as an area of "growing concerns". "Energy trade is increasingly constricted, with resulting market distortions. Principles are applied selectively and what is preached is not necessarily practised," he said, supporting "adjustments" and "resilient solutions".

"Multipolarity is not just here to stay but to grow. All these warrant serious global conversations," he said. He expressed India's commitment to enhancing maritime cooperation in the ASEAN region.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS):

- स्थान: कुआलालंपुर, मलेशिया (2025)
- सदस्य: ASEAN + 8 (भारत, अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, रूस)
- उद्देश्य: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक स्थिरता पर चर्चा।

भारत की स्थिति:

- अमेरिका द्वारा घोषित गाज़ा शांति पहल का समर्थन।
- यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र अंत का आह्वान, ताकि खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थिर हो सकें।

जयशंकर के भाषण की प्रमुख थीम:

- वैश्विक संघर्षों का असर खाद्य, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला पर।
- गैर-भेदभावपूर्ण व लचीले वैश्विक व्यापार की आवश्यकता।
- भारत का समर्थन बहुध्रुवीयता (multipolarity) और साझा वैश्विक समाधान के पक्ष में।

भारत–आसियान फोकस:

- आसियान क्षेत्र में समुद्री संपर्क और सहयोग को गहराई देना।
- इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) और एक्ट ईस्ट नीति से समन्वय।

भारत–अमेरिका संबंध संदर्भ:

- जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से।
- भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ प्रतिबंधों के कारण संबंधों में हल्का तनाव।

मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

1. भारत की संतुलित कूटनीति: भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी है — वह शांति का समर्थन करता है पर किसी गुट के साथ नहीं जुड़ता। गाज़ा और यूक्रेन दोनों ही मामलों में भारत ने संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है, टकराव को नहीं।

2. ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा आयाम: यूक्रेन और गाज़ा जैसे संघर्षों से अनाज निर्यात, उर्वरक आपूर्ति और ऊर्जा कीमतें प्रभावित होती हैं। भारत का बयान विकासशील देशों की चिंता दर्शाता है जो स्थिर वैश्विक बाज़ारों पर निर्भर हैं।

3. भू-राजनीतिक संतुलन: EAS में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि वह आसियान की केंद्रीयता और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। भारत ने अमेरिका, रूस और पश्चिम एशिया सभी के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखा है — यह "मल्टी-अलाइनमेंट" की नीति है, न कि तटस्थता।

4. आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ: अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए तेल आयात टैरिफ को भारत आर्थिक दबाव (economic coercion) के रूप में देखता है। भारत विविध ऊर्जा साझेदारियों और लचीली सप्लाई चेन की वकालत करता है।

5. बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था: जयशंकर का कथन — "Multipolarity is not just here to stay but to grow" — इस बात का संकेत है कि भारत एक ऐसे बहुध्रुवीय विश्व की दिशा में अग्रसर है, जहाँ कोई एक शक्ति हावी न हो और देश विषय-आधारित साझेदारी (issue-based partnership) अपनाएँ।

निष्कर्ष

- 20वें EAS में भारत ने वैश्विक शांति, गाज़ा शांति योजना, और यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समाधान की पैरवी की।
- भारत का दृष्टिकोण एक शांतिपूर्ण, बहुध्रुवीय और संतुलित विश्व व्यवस्था की दिशा में है, जो राष्ट्रीय हितों को वैश्विक स्थिरता से जोड़ता है। यह "एक्ट ईस्ट नीति" और "इंडो-पैसिफिक एंगेजमेंट" की भावना को भी आगे बढ़ाता है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: भारत द्वारा शुरू की गई "Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI)" मुख्यतः केंद्रित है —

(a) समुद्री सुरक्षा और संपर्कता

(b) मानवीय सहायता वितरण

(c) आसियान देशों के लिए निर्यात संवर्धन

(d) मत्स्य पालन विकास

Ans: a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब रणनीतिक इंडो-पैसिफिक जुड़ाव का रूप ले रही है। आसियान मंचों पर हाल के कूटनीतिक संवादों के संदर्भ में इस रूपांतरण का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Daily News Analysis

Page 07 : GS 3 : Science and Tech

हर वर्ष स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रो. **जॉन इओनिडिस (John Ioannidis)** द्वारा **Elsevier के Scopus डाटाबेस** पर आधारित एक सूची जारी की जाती है, जिसमें विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को स्थान दिया जाता है। यह सूची वैश्विक अकादमिक जगत में प्रतिष्ठा और चर्चा का विषय बन जाती है।

2025 की सूची में **6,239 भारतीय वैज्ञानिकों** को शामिल किया गया, जिससे देशभर में कई संस्थानों ने इसे "उपलब्धि" के रूप में मनाया। हालाँकि, गहराई से विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इस सूची की **कार्यप्रणाली (methodology)** वैज्ञानिक गुणवत्ता या प्रभाव का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि यह **साइटेशन-आधारित मापदंडों (citation metrics)** पर अत्यधिक निर्भर है, जो आसानी से विकृत या दुरुपयोग किए जा सकते हैं।

Stanford/Elsevier's rank list: why all that glitters is not gold

Scientists are often evaluated by the number of citations they have garnered. However, there has been a naive assumption that scientists always cite only good-quality papers, which in turn has fed the notion that a paper's citation number is indicative of its impact. But this needn't always be true

Swaminathan S

Stanford University professor John Ioannidis recently published the latest version of the list of the world's top 2% of scientists. Its release every year causes much excitement among scientists and their institutions. And every year for a few weeks after, hardly a day passes without multiple announcements of the presence of Indian scientists on this list by many institutions, from well-known to obscure, on various media platforms. They tout the honour as recognition of their scientific excellence; indeed, many of these institutes even claim the achievement wouldn't have been possible without their role in creating and sustaining an enabling research environment.

The 2025 list was published in September and ranked around 2.3 lakh scientists worldwide – themselves filtered out of a pool of 2.2 crore. This supposedly exalted fraction, which included several Nobel laureates, also counted 6,239 scientists from India. This number has been steadily increasing over the last few years.

The vast majority of scientific research today builds on the work of others.

Link to quality

The top 10 scientists from India in the 2025 list have been ranked 288 to 952 and are with Muthayammal Engineering College (Tamil Nadu), University of Petroleum and Energy Studies (Uttarakhand), Thapar Institute of Engineering & Technology (Punjab), Indian Institute of Toxicology Research (Uttar Pradesh), Sikkim University, National Institute of Mental Health and Neurosciences (Karnataka), Saveetha School of Engineering (Tamil Nadu), Government Degree College Pulwama (Jammu & Kashmir), and S.V. National Institute of Technology (Gujarat).

This picture was more or less the same in 2024, when the top 10 Indian scientists were ranked 163 to 1568 and lesser-known institutions dominated.

Curiously, six of the seven science Nobel laureates on the list ranked 1,373-28,782 – far lower than the lowest ranked (top 10) Indian scientist. Indeed, to say that it is pretty astounding that even the lowest Indian scientist (top 10) performed way better on this list than all but one of the Nobel laureates is an understatement.

Whether this gap is actually linked to research quality in a meaningful way is, however, a separate question – one also elicited by the fact that the top 10 scientists are not affiliated with Indian research centres generally associated with excellent R&D. To understand this disconnect, we need to understand what scientific research is and how it is routinely evaluated in the prevailing academic ecosystem.

Standing on shoulders

Scientific research begins when scientists have a question about some observation that has caught their interest. They formulate a hypothesis and test it with experiments. Depending on the needs of each experiment, they may devise tools, interact with other scientists to get different perspectives, gather evidence, and analyse it to draw conclusions. Then they write up their findings in reports, commonly known as papers, which are reviewed by their peers and published in scientific journals. These papers bear the names of the scientists, so the scientists are also called authors.

The vast majority of scientific research today builds on the work of others. So the authors of a paper cite an older paper – like an acknowledgment that also adds one more link to the chain of knowledge – where its findings are relevant in their current work. When one paper has been cited by another paper once, it's said to have accrued one citation.

Scientists' work is often evaluated by the number of citations their papers have garnered. But there is a catch: there has been a naive assumption for a while now that scientists always only cite good-quality papers, which in turn has fed the notion that a paper's citation number is indicative of its impact. But there is no need for this to always be true.

Evaluating science

Prof. Ioannidis prepares his list based on a global database of published research called Scopus. It is owned by Elsevier, a publishing company that is often accused of taking advantage of the "publish or perish" culture in academia to earn profits rivalling those of Google and Microsoft.

For his analysis, Prof. Ioannidis developed a composite score, called c-score, for each scientist in Scopus and ranked them in descending order of their c-scores.

The c-score gives equal weightage to multiple parameters, including the total number of citations, the h-index (a metric that links the citation number to the number of papers published by a scientist), the number of papers, the order of authors in papers, co-authorships, and so on. The ranking also includes scientists across several different fields and sub-fields.

Like many metrics that flatten the multi-dimensional enterprise that is scientific research into one-dimensional numbers, the c-score is a vanity metric. Researchers and employers should focus on good research, and the research establishment should focus on facilitating that – rather than chasing numbers

Comparing scientists in this way, across a breadth of enterprises, is generally considered problematic, like comparing apples to oranges.

Also, contrary to popular perception, Stanford University neither participates in the ranking process nor endorses the list. The effort is the individual initiative of Prof. Ioannidis.

Nobel Prize v. c-score

To understand why Indian scientists from little known research centres rank above Nobel laureates on the list, the c-score is a good starting point. While Prof. Ioannidis and some others have said it provides a more comprehensive snapshot of a scientist's impact, it has serious limitations. It gives extra weight to papers where the scientist is the first, single, or last author, assuming that these positions imply major intellectual contribution, but this practice is not uniform across fields; it doesn't account for differences in citation practices between fields; it assumes the Scopus database covers all disciplines equally (it doesn't); and it ignores qualitative impact.

The final effect is for a scientist's c-score to be divorced from the actual scientific content of their work, especially in terms of its quality, validity, and contribution to science and society. Indeed, despite their other flaws, the process of identifying Nobel prize-winning scientists takes into account all that the c-score misses.

As with all metrics, the c-score can also be gamed, especially by individuals who pre-agree to cite each other's papers irrespective of the quality of their own papers or whether the citations are appropriate and warranted. This much is evident from the impossibly high levels of productivity – 1-2 papers per week – of many highly ranked Indian scientists. The rankings also don't account for papers that are later retracted for misconduct, such as by including a penalty in the c-score formula. Indeed, the Scopus database itself includes many dubious journals and publishers with little respect for research ethics.

Without understanding the c-score in this way, one is liable to interpret Indian scientists outranking Nobel laureates in Prof. Ioannidis' list as the former's overlooked greatness – but one shouldn't be forgiven for doing so. Like many other metrics that flatten the multi-dimensional enterprise that is scientific research into one-dimensional numbers, the c-score is fundamentally a vanity metric. Instead, researchers and their employers should focus on doing good research, and the research establishment should focus on facilitating that – rather than chase numbers.

(Swaminathan S. is retired professor, BITS Pilani – Hyderabad, and former scientist at ICGEB, New Delhi. ssn225@gmail.com)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रमुख तथ्यात्मक बिंदु

स्टैनफोर्ड/एल्सेवियर वैज्ञानिक रैंकिंग:

- तैयार की गई: **प्रो. जॉन इओनिडिस**, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा।
- डेटा स्रोत: **Elsevier का Scopus डाटाबेस** (वैश्विक शोध सूचकांक)।
- कुल लगभग **2.3 लाख वैज्ञानिक** (2.2 करोड़ में से) को रैंक किया गया।
- **C-score** नामक मिश्रित संकेतक (composite metric) के आधार पर रैंकिंग की जाती है।
- यह **स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूची नहीं** है; यह इओनिडिस का स्वतंत्र कार्य है।

C-score क्या है?

यह एक संयुक्त सूचकांक है, जो निम्नलिखित पर आधारित है —

- कुल **साइटेशन (citations)**
- **H-index** (कितने शोधपत्रों को कितनी बार उद्धृत किया गया)
- **लेखक क्रम** (पहला, एकल या अंतिम लेखक)
- **सह-लेखन पैटर्न (co-authorship patterns)**
- कई विषयों में तुलनात्मक रैंकिंग प्रदान करता है।

भारत की स्थिति (2025):

- 6,239 भारतीय वैज्ञानिक सूची में शामिल।
- शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों की रैंकिंग 288 से 952 के बीच।
- कई वैज्ञानिक अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध संस्थानों से (जैसे मुथायम्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, UPES, थापर यूनिवर्सिटी)।

Scopus और Elsevier की आलोचना:

- Elsevier पर आरोप है कि वह अकादमिक जगत के "**publish or perish**" दबाव से लाभ उठाता है।
- Scopus में कई **संदिग्ध (dubious)** जर्नल शामिल हैं, और विषयवार कवरेज असमान है।

नोबेल विजेताओं की स्थिति:

- कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं की रैंक 1,373 से 28,782 के बीच है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि **साइटेशन की संख्या हमेशा वास्तविक वैज्ञानिक प्रभाव को नहीं दर्शाती।**

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक बिंदु

1. साइटेशन आधारित मूल्यांकन की समस्या:

- यह मानना कि "**अधिक साइटेशन = बेहतर गुणवत्ता**" एक भ्रामक धारणा है।
- कई पेपर विवाद, आलोचना या असफल प्रतिकृति (replication failure) के कारण भी अधिक उद्धृत होते हैं।
- विभिन्न विषयों में उद्धरण पैटर्न अलग-अलग होते हैं, जिससे **क्रॉस-डिसिप्लिन तुलना अवैध (invalid)** हो जाती है।

2. C-score मॉडल की खामियाँ:

- **संख्यात्मक संकेतकों पर अत्यधिक निर्भरता** वैज्ञानिक उत्कृष्टता को "वैनिटी मीट्रिक" बना देती है।
- यह मानना कि लेखक का क्रम योगदान को दर्शाता है, हर क्षेत्र में सही नहीं है।
- **वापस लिए गए पेपर (retracted papers)** या **अनैतिक प्रकाशन** को दंडित नहीं करता।
- शोध के **सामाजिक या व्यावहारिक प्रभाव** को ध्यान में नहीं रखता।

3. शैक्षणिक मूल्यांकन की संरचनात्मक समस्या:

- "**Publish or perish**" संस्कृति गुणवत्ता की जगह मात्रात्मकता को बढ़ावा देती है।
- कुछ शोधकर्ता **आपसी साइटेशन समझौते** या **स्वयं-साइटेशन** के माध्यम से रैंक बढ़ाते हैं।
- इससे गलत प्रोत्साहन पैदा होता है, जो **ईमानदारी और नवाचार** की जगह **दिखावे** को पुरस्कृत करता है।

4. नोबेल पुरस्कार बनाम मीट्रिक:

- नोबेल पुरस्कार **मौलिकता, गहराई और परिवर्तनकारी प्रभाव** को मान्यता देते हैं — जो संख्यात्मक रूप में नहीं मापे जा सकते।
- नोबेल विजेताओं का निम्न रैंक पर होना यह दर्शाता है कि **मीट्रिक आधारित मूल्यांकन वास्तविक वैज्ञानिक योगदान को विकृत कर सकता है।**

5. भारत के लिए नीतिगत निहितार्थ:

- भारतीय संस्थानों को **मीट्रिक-आधारित मान्यता** से हटकर **सहकर्मी समीक्षा (peer review)**, **नैतिक अनुसंधान संस्कृति**, और **सामाजिक प्रभाव आधारित मूल्यांकन** को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **शोध प्रशासनिक सुधारों** की आवश्यकता है — गुणवत्ता आश्वासन, मेंटरशिप और नैतिक प्रशिक्षण के साथ।

6. नैतिक और संस्थागत दृष्टिकोण:

- रैंकिंग और मीट्रिक की अंधी दौड़ वैज्ञानिक ईमानदारी को कमजोर कर सकती है।
- केवल सूची में शामिल होने पर संस्थागत उत्सव मनाना **"institutional vanity"** को दर्शाता है, न कि वास्तविक उत्कृष्टता को।

निष्कर्ष

- स्टैनफोर्ड/एल्सेवियर रैंकिंग कोई आधिकारिक विश्वविद्यालय मान्यता नहीं है, बल्कि Scopus डेटा पर आधारित एक स्वतंत्र सूची है। इसका **C-score** मॉडल साइटेशन से जुड़े कई तत्वों को जोड़ता है, परंतु यह **गुणात्मक पहलुओं** को नहीं माप पाता।
- यह मुद्दा इस बात पर प्रकाश डालता है कि **मीट्रिक आधारित मूल्यांकन सीमित और भ्रामक** हो सकता है। वैज्ञानिक उत्कृष्टता को संख्याओं में नहीं, बल्कि **नवाचार, सत्यनिष्ठा और सामाजिक प्रभाव** से आंका जाना चाहिए।

Daily News Analysis

Ques. क्या भारत के शैक्षणिक संस्थानों को स्टैनफोर्ड/एल्सेवियर जैसी रैंकिंग को उत्सव की तरह मनाना चाहिए? कारण दीजिए और उपयुक्त नीतिगत सुझाव प्रस्तुत कीजिए। **(250 Words)**

Daily News Analysis

Page : 08 : GS 2 : Governance & Social Justice / Prelims

भारत में भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों को नियंत्रित करने के प्रयास 1954 में पारित ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (ऑब्जेक्शनबल एडवर्टाइजमेंट्स) एक्ट (DMRA) से शुरू हुए थे। यह अधिनियम ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है जो यह दावा करे कि वह डायबिटीज़, कैंसर, या यौन विकार जैसी 54 बीमारियों का इलाज कर सकता है।

- लेकिन आज के डिजिटल युग और बिग टेक प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे Google, Meta, YouTube, Amazon आदि) के प्रसार के साथ यह कानून कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय कानूनों के बावजूद ये वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म भ्रामक और अवैध विज्ञापनों को बढ़ावा देकर लाभ कमा रहे हैं — जिससे प्रवर्तन, अधिकार-क्षेत्र और जवाबदेही में गंभीर कमी उजागर होती है।

Daily News Analysis

Big Tech's contempt for Indian public health

Since 1927, when the topic of drug regulation was first discussed in the Council of State after Sir Haroon Jaffer sought a resolution regarding the "control of the craze for medicinal drugs", the issue of advertisements of drugs claiming to have a therapeutic effect on humans has been a serious public health concern.

It took 27 years before India tackled the issue through the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act (DMRA), 1954. This law prohibits any advertisements of any drugs, whether approved or not by the regulator, for a list of 54 medical conditions. For example, the law prohibits the advertisement of any drug for the treatment of diabetes, regardless of whether its efficacy has been clinically established.

The advent of Internet-based advertising

A lot has changed since 1954, especially in the world of advertisement. The Internet and the rise of Big Tech platforms, in the nature of search engines, social media platforms, video-sharing platforms and online marketplaces for goods, have steadily eaten into the traditional avenues of advertising in print and broadcast formats. This shift has not only upended print journalism across the world which was reliant on advertisements, but also made it far tougher for governments across the world to police advertisements published on these Big Tech platforms headquartered in the United States.

In a deep dive on the advertising policies and practices of the most popular American Big Tech platforms in India, we were astonished to note that not a single one of them warns advertisers not to submit for publication, advertisements which are in violation of the DMRA. Thus, it is no surprise that all Big Tech platforms routinely publish a wide variety of misleading advertisements, especially for ayurvedic and homeopathic products. For example, a simple search for "ayurveda" + "blood pressure tablets" or "homeopathy" + "diabetes" on the most popular search engine and online market place in India will throw up a variety of advertisements on these platforms under the "sponsored" tag, indicating that they have been paid for by advertisers.

One of the most popular social media platforms features video advertisements by a notorious godman with the claim of being able to cure all kinds of diseases using ayurvedic products.

Similarly, a search of the online ad-libraries of these Big Tech platforms reveals a long list of offending advertisements, including those for cow-urine based products to treat cancers; these advertisements were supported by a charitable programme run by the Big Tech platform. All these advertisements are in violation of the DMRA.

None of these Big Tech platforms runs similar advertisements in the United States for ayurvedic and homeopathic products. The policies of these platforms for advertisements for health-related products to be displayed to users based in the U.S. are elaborate, with some even having pre-screening mechanisms that are meant to ensure compliance with tough American laws; these laws prohibit advertisements for therapeutic claims that are not approved by the drug regulator. In the U.S., violation of American law can attract swift criminal prosecution.

Dinesh S. Thakur
is the author of 'The Truth Pill: The Myth of Drug Regulation in India' (Simon & Schuster)

Prashant Reddy T.
is the co-author of 'The Truth Pill: The Myth of Drug Regulation in India' (Simon & Schuster)

The rise in misleading advertisements by popular platforms is also linked to the immunity that Big Tech enjoys in India

Disregard for Indian law

So, what explains Big Tech's brazen disregard of Indian laws such as the DMRA?

The first reason could be the traditional contempt that American corporations, dating back to Union Carbide, have shown for the lives of Indians. It is possible that this contempt arises from systemic racism that afflicts the management of American corporations, wherein Indian lives are not considered to be comparable to American lives.

The second is that Big Tech has escaped serious punishment earlier for violation of another law called The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (PNDT). This law prevents advertisements for products and services related to determination of the sex of the unborn foetus. A PIL was filed in 2008 by an activist before the Supreme Court of India pointing out how Big Tech platforms were in brazen violation of this law. Before the Court, Big Tech was evasive on the point of instituting proactive measures to block such advertisements, insisting that it was under an obligation to remove offending advertisements only if government or others informed them about such violations. To make a long story short, Big Tech fell back into a familiar pattern of deception, by claiming that it was the "intermediary" not the "publisher".

Under Indian law, intermediaries have qualified immunity from legal liability for content generated by their users because they are presumed to lack knowledge of each piece of content that is posted by users. But when it comes to advertisements, Big Tech knows very well that it is the "publisher" and not the "intermediary". The marketing teams of Big Tech on the ground in India actively pitch for advertisements, sign contracts with advertisers and accept payments for the purpose of displaying the advertisement on their platform. They have complete knowledge about these advertisements; hence, they are publishers and not mere intermediaries who can claim immunity under the law.

The PIL regarding the violation of the PNDT languished for nine years before ending with the usual insipid orders for the creation of a government committee to look into the issue. Criminal prosecution was never ordered by the Court despite being the prescribed punishment under the PNDT Act. The abject failure of the Court to enforce the law by ordering criminal prosecutions, and the process which frustrates litigants who represent public interest in such cases undoubtedly emboldened Big Tech's sense of impunity in India.

The third reason is that Big Tech is aware that the U.S. government would never extradite top managerial personnel from America to face criminal prosecution in India for violating the DMRA. Big Tech's employees running Indian subsidiaries located on Indian territory cannot be prosecuted because the Indian subsidiary is a different legal entity from its parent company located in the U.S., which legally owns and operates the advertising platforms in India. Undoubtedly, this implicit immunity is what fuels Big Tech's bad behaviour in India.

The need for reforms

Tackling Big Tech's dangerous violations of the DMRA should be an urgent priority in a country such as India which self-prescribes medicines and has an inherent bias toward "nationalist" tropes.

Registering criminal complaints before courts of competent jurisdiction against the management of these platforms would be a good first step. If Big Tech declines to produce its competent managerial personnel before an Indian court to face these charges, the government will be compelled to ensure reforms that will make Big Tech answerable to Indian sovereignty.

It is perhaps time for India to take a page from the new American playbook to regulate Tik Tok and create new regulatory mechanisms. This is to ensure that the managerial personnel responsible for creating and enforcing content and advertising related policies in India are Indian citizens who are based in Indian territory and answerable to Indian courts. Anything short of the threat of jail time for key managerial personnel will fail to ensure that Big Tech's complies with Indian law.

Further, a failure of Big Tech to comply with these legal requirements should result in a revocation of the immunity granted to Big Tech under Indian intermediary laws from legal action for user-generated content. Big Tech cannot be allowed to enjoy these benefits under Indian law if it does not enforce relevant Indian laws to protect public health in India.

प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रमुख बिंदु

ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (ऑब्जेक्शनबल एडवर्टाइजमेंट्स) एक्ट, 1954 (DMRA):

- उद्देश्य: "चमत्कारी" या "जादुई" गुणों का दावा करने वाले भ्रामक दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाना।
- यह सभी प्रकार के विज्ञापनों पर लागू होता है, चाहे दवा अनुमोदित हो या नहीं।
- 54 बीमारियों (जैसे मधुमेह, कैंसर, नपुंसकता आदि) के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध।

बिग टेक और डिजिटल विज्ञापन:

- Google, Meta, YouTube, Amazon आदि पेड हेल्थ विज्ञापनों के प्रकाशक (publishers) के रूप में कार्य करते हैं।
- ये प्लेटफ़ॉर्म आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या अप्रमाणित उत्पादों के झूठे दावे वाले विज्ञापन दिखाते हैं — जो DMRA का उल्लंघन है।
- अमेरिका में ऐसे विज्ञापन सख्त पूर्व-जाँच (pre-screening) और कानूनी अनुपालन के बिना नहीं चलाए जा सकते।

PNDT अधिनियम, 1994 का उल्लंघन:

- प्रि-कंसेप्शन एंड प्रि-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 लिंग-निर्धारण और उससे संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाता है।
- 2008 में एक जनहित याचिका (PIL) के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा जब इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर लिंग-निर्धारण से जुड़े विज्ञापन पाए गए।
- कंपनियों ने "intermediary (मध्यस्थ)" होने का दावा कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।

कानूनी स्थिति – प्रकाशक (Publisher) बनाम मध्यस्थ (Intermediary):

- भारतीय कानून के अनुसार intermediary उपयोगकर्ता-जनित सामग्री (user-generated content) के लिए सीमित रूप से जिम्मेदार होता है।
- लेकिन पेड विज्ञापन के मामले में प्लेटफ़ॉर्म "publisher" माने जाते हैं, क्योंकि वे विज्ञापन मांगते हैं, अनुमोदन देते हैं, और उससे लाभ कमाते हैं।

अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) की समस्या:

- अमेरिकी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियाँ (subsidiaries) कानूनी रूप से स्वतंत्र संस्थाएँ होती हैं, जिससे मूल कंपनी पर मुकदमा चलाना कठिन होता है।
- Extradition सीमाएँ अमेरिकी अधिकारियों को भारतीय अदालतों से बचाव का अवसर देती हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु विश्लेषणात्मक बिंदु

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य और भ्रामक डिजिटल विज्ञापन: भारत में स्व-चिकित्सा (self-medication) की प्रवृत्ति और पारंपरिक उपचारों में विश्वास के कारण जनता भ्रामक विज्ञापनों के प्रति अधिक संवेदनशील है। बिग टेक का भारतीय कानूनों जैसे DMRA का पालन न करना नागरिकों को गलत स्वास्थ्य दावों से बचाने के प्रयासों को कमजोर करता है।

2. नियामक और कानूनी चुनौतियाँ:

- मौजूदा कानून (DMRA, PNDT) डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।
- प्रवर्तन तंत्र (enforcement) कमजोर है — पूर्व-जाँच नहीं होती, निगरानी ढीली है, और न्यायिक प्रक्रिया धीमी।
- PNDT मामले में सुप्रीम कोर्ट की धीमी कार्रवाई ने कंपनियों को लापरवाह रवैया अपनाने का अवसर दिया।

3. नैतिकता और संप्रभुता का प्रश्न:

- अमेरिका में कड़े नियमों का पालन और भारत में ढिलाई दिखाना "कॉर्पोरेट नस्लवाद" और "डिजिटल उपनिवेशवाद (Digital Colonialism)" को दर्शाता है।
- यह दिखाता है कि वैश्विक टेक कंपनियाँ विकासशील देशों के नियामक ढाँचे से ऊपर अपने हितों को रखती हैं।

4. नीतिगत सुधार सुझाव:

- भारत में बिग टेक कंपनियों के प्रबंधकीय अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने की व्यवस्था।
- यदि प्लेटफ़ॉर्म भारतीय कानूनों का पालन न करें तो intermediary immunity (मध्यस्थ संरक्षण) रद्द किया जाए।
- विज्ञापन और कंटेंट नीति से जुड़े प्रमुख अधिकारी भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हों (जैसे अमेरिका ने TikTok पर लागू किया)।
- ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी हेतु स्वतंत्र डिजिटल नियामक संस्था बनाई जाए।

5. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सूचना की अखंडता:

- भ्रामक विज्ञापन कमज़ोर वर्गों को असुरक्षित या अप्रभावी चिकित्सा अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- डिजिटल क्षेत्र में विश्वसनीयता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा बनाए रखने के लिए सशक्त शासन (governance) अनिवार्य है।

निष्कर्ष

- DMRA (1954) और PNDT (1994) अधिनियम भारत में चिकित्सा विज्ञापनों के नियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परंतु बिग टेक प्लेटफ़ॉर्म्स की अनुपालनहीनता और प्रवर्तन की कमी ने इन्हें डिजिटल युग में अप्रभावी बना दिया है।
- भारत को अपने नियामक ढाँचे को Big Tech की जवाबदेही, डिजिटल संप्रभुता और उपभोक्ता सुरक्षा के अनुरूप अद्यतन करना होगा।
  जब तक प्रकाशक और मध्यस्थ की कानूनी परिभाषा स्पष्ट नहीं होती और उल्लंघन पर कठोर दंड नहीं दिए जाते, तब तक जनता का स्वास्थ्य जोखिम में रहेगा।

Daily News Analysis

UPSC Prelims Practice Question

Ques : निम्नलिखित में से कौन-सा कथन "ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (ऑब्जेक्शनबल एडवर्टाइजमेंट्स) एक्ट, 1954" के संबंध में सही है?

(a) यह केवल अनुमोदित दवाओं के विज्ञापन की अनुमति देता है।

(b) यह सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है, चाहे दवा अनुमोदित हो या नहीं।

(c) यह केवल प्रसारण माध्यम (broadcast media) के विज्ञापनों पर लागू होता है।

(d) यह केवल एलोपैथिक दवाओं पर लागू होता है।

Ans: b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: डिजिटल उपनिवेशवाद और नया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट: बिग टेक की नीतियाँ भारत की संप्रभुता और नागरिक सुरक्षा को कैसे कमजोर करती हैं? **(150 Words)**

Daily News Analysis

Page 10 : GS 1 : Indian Society / Prelims

भारत में भाषाई विविधता (linguistic diversity) तेजी से घट रही है। यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, भारत दुनिया में उन देशों में अग्रणी है जहाँ सबसे अधिक भाषाएँ और बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। पिछले 50 वर्षों में भारत की **220 से अधिक भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं** (स्रोत: डी. जी. राव, केंद्रीय भाषा संस्थान)। इसी परिप्रेक्ष्य में **डोगरी भाषा**, जो जम्मू क्षेत्र की मातृभाषा है, एक महत्वपूर्ण अध्ययन का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

Is the Dogri language losing resonance in India?

Is the Dogri language declining at the same rate across rural and urban landscapes in the Jammu region?

Rohan Qurashi
Heena Chaudhary

The story so far:

Human society is rapidly moving towards the extinction of its linguistic heritage. According to one report by UNESCO, India has topped the list of countries with the maximum number of dialects on the verge of extinction. According to D.G Rao, former Director of the Central Institute of Languages, India has lost over 220 languages in the last 50 years.

Is Dogri in decline?

In recent years, growing concern has emerged over the gradual decline of the Dogri language in the Jammu region. Globalisation, migration, and the pursuit of economic opportunity often encourage speakers to prioritise widely used languages, while regional ones fade into disuse. Political choices and a lack of active interest among native speakers further deepen this crisis. Against this backdrop, Dogri finds itself at a crossroads. Although the J&K Official Languages Bill, 2020 gave it the long-overdue recognition as one of the Union Territory's five official languages, its status on paper has not translated into meaningful presence on the ground. Unlike other regional languages that have secured space in school curricula or administrative use, Dogri remains largely absent from formal education.

Why is Dogri not being spoken?

The decline of Dogri in the Jammu region can be looked at through three critical lenses – government policy, generational perspectives, and the rural-urban divide.

One of the central reasons for the decline of Dogri lies in the absence of sustained government support. Unlike Urdu, Kashmiri, and Hindi, Dogri had to wait until 2003 for constitutional recognition. This long delay meant that by the time Dogri gained official status, it had already fallen behind in terms of institutional backing and visibility. A survey conducted by the authors further underscores this policy gap. The research employed a random sampling method, selecting households at intervals of three to four units to ensure representativeness. The sample was distributed across 20 different locations in the Jammu region; 130 people filled the survey form completely.

Nearly half of the respondents (48%) from the Jammu region believe that the government has failed to provide adequate policy support for Dogri. Another 43.2% felt that the language offers little relevance for employment prospects or career advancement. Additionally, the survey revealed a stark generational divide in Dogri proficiency. The oldest respondents, those aged 60 and above, displayed the strongest connection to the language, with full proficiency in speaking and an intermediate score in reading and writing. However, among respondents aged 41-60, writing proficiency dropped sharply to just 0.25%, reflecting the gradual erosion of literacy in the language. Respondents under 20 years of age show 0% proficiency in reading and writing Dogri.

The survey also revealed a striking contrast between rural and urban populations in terms of Dogri language usage. Approximately 56% of respondents from rural areas actively speak Dogri, with around 15% demonstrating the ability to write it. In contrast, among urban respondents, only 45% reported speaking Dogri, and only 4% had any proficiency in writing it.

What is the way ahead?

To address India's linguistic crisis, two challenges must be addressed. First is technical – with the 2021 Census on hold, one lacks updated data on how many languages are endangered, and where urgent intervention is needed. Without this knowledge, both awareness and policy remain adrift. Secondly, one must shed the mindset that equates English alone with progress. The decolonisation of linguistics is the larger task at hand.

Rohan Qurashi is a research student at St. Stephen's College, Delhi. Heena Chaudhary is a Phd scholar.

THE GIST

- Globalisation, migration, and the pursuit of economic opportunity often encourage speakers to prioritise widely used languages, while regional ones fade into disuse.
- The decline of Dogri in the Jammu region can be looked at through three critical lenses — government policy, generational perspectives, and the rural-urban divide.
- The survey also revealed a striking contrast between rural and urban populations in terms of Dogri language usage.

1. क्या डोगरी भाषा क्षरण की ओर बढ़ रही है?

हाँ। हालाँकि **डोगरी जम्मू-कश्मीर की पाँच आधिकारिक भाषाओं** (2020 के J&K Official Languages Bill के तहत) में से एक है, परंतु इसका वास्तविक उपयोग बहुत सीमित है।

मुख्य कारण:

- **प्रतीकात्मक मान्यता**, न कि व्यवहारिक प्रयोग — स्कूलों, कार्यालयों या प्रशासन में बहुत कम उपयोग।
- **वैश्वीकरण और प्रवास** के कारण अंग्रेज़ी और हिंदी को "आर्थिक रूप से लाभदायक" भाषा माना जाने लगा है।
- **राजनीतिक उपेक्षा** और **समुदाय की कम भागीदारी** ने भाषा के पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया है।

2. क्षरण के प्रमुख कारण

(a) सरकारी नीतिगत खामियाँ (Government Policy Gaps)

- डोगरी को संवैधानिक मान्यता **2003 में** (संविधान की आठवीं अनुसूची में) ही मिली।
- न पर्याप्त फंडिंग, न पाठ्यक्रम में स्थायी रूप से शामिल किया गया, न ही प्रचार-प्रसार के ठोस प्रयास हुए।

सर्वे डेटा:

- 48% उत्तरदाताओं का मत: नीतिगत सहयोग अपर्याप्त।
- 43.2% का मत: डोगरी का करियर में कोई प्रासंगिक उपयोग नहीं।

(b) पीढ़ीगत अंतर (Generational Divide)

आयु वर्ग	बोलने में दक्षता	पढ़ने/लिखने में दक्षता
60 वर्ष से ऊपर	उच्च	मध्यम
41–60 वर्ष	घटकर मात्र 0.25% लेखन दक्षता	
20 वर्ष से नीचे	पढ़ने-लिखने में शून्य दक्षता	

➞ यह संकेत करता है कि भाषा का पीढ़ियों के बीच प्रसारण (linguistic transmission) टूट रहा है।

(c) **ग्रामीण–शहरी अंतर (Rural–Urban Divide)**

श्रेणी	डोगरी बोलने वाले (%)	डोगरी लिखने वाले (%)
ग्रामीण	56%	15%
शहरी	45%	4%

ग्रामीण क्षेत्र डोगरी के **अंतिम मजबूत गढ़** हैं, लेकिन वहाँ भी साक्षरता तेजी से घट रही है।

3. व्यापक निहितार्थ (Broader Implications)

डोगरी की स्थिति भारत की एक **बड़ी प्रवृत्ति (pattern)** को दर्शाती है — जहाँ क्षेत्रीय भाषाएँ **शहरीकरण**, **अंग्रेज़ी-माध्यम शिक्षा**, और **आधुनिक सफलता की संकीर्ण परिभाषा** के सामने टिक नहीं पा रही हैं।

4. आगे की राह (The Way Forward)

- **जनगणना 2021 के अद्यतन आंकड़े** शीघ्र जारी हों, ताकि संकटग्रस्त भाषाओं का सटीक मानचित्रण हो सके।
- **शिक्षा, मीडिया और प्रशासन** में डोगरी को एकीकृत (integrate) किया जाए ताकि इसका सामान्यीकरण (normalisation) हो।
- **स्थानीय गौरव और सामुदायिक पहल** को प्रोत्साहित किया जाए — लोक साहित्य, लोक उत्सव, नाटक आदि के माध्यम से।
- **मानसिकता में बदलाव:** "**अंग्रेज़ी = प्रगति**" नहीं, बल्कि "**भाषाई विविधता = सांस्कृतिक शक्ति**" है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques : निम्नलिखित में से डोगरी भाषा के बारे में कौन-सा कथन सही है?

(a) डोगरी को 1950 में संवैधानिक मान्यता मिली थी।

(b) डोगरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया था।

(c) डोगरी हिमाचल प्रदेश की पाँच आधिकारिक भाषाओं में से एक है।

(d) जम्मू के शहरी विद्यालयों में डोगरी व्यापक रूप से शिक्षण की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।

Ans: b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: सरकारी नीतिगत खामियाँ और पीढ़ियों के बीच आ रहे बदलाव किस प्रकार डोगरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के क्षरण (erosion) में योगदान दे रहे हैं? **(150 Words)**

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 08 Editorial Analysis

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

A start for North-South carbon market cooperation

On September 17, 2025, the European Union (EU) and India set out a new comprehensive strategic agenda in their joint communication. Called the New Strategic EU-India Agenda, it primarily addresses five pillars on which their partnership will be enhanced: prosperity and sustainability; technology and innovation; security and defence; connectivity and global issues, and enablers across pillars. Buried in the section on clean transition is a critical line that the EU will link the Indian Carbon Market (ICM) with the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

In plain terms, carbon prices paid in India will be deducted from CBAM levies at the EU border. This is a breakthrough. It could prevent Indian exporters from being penalised twice and reward early decarbonisation. However, major barriers still plague its operationalisation. Unless addressed, they will stall this integration before it delivers real gains.

Underdeveloped Indian carbon market

India's Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), commonly referred to as ICM, is still an evolving architecture. Unlike the EU Emissions Trading System (ETS), which has a two decade record of robust auction structure, cap-setting processes, and independent verification, India's scheme is built on fragmented foundations. Current credits are often based on intensity improvements or project-based offsets, not absolute caps on emissions, wherein the ICM is moving. The CBAM, however, requires a tonne-for-tonne accounting of embedded carbon in goods. Without legally binding caps and strong penalties for non-compliance, EU regulators will treat Indian credits as second class.

There is also no current institutional equivalent in India to the EU's independent regulators or emissions registries that guarantee market integrity. In effect, the EU cannot "deduct" Indian carbon prices unless it is confident that the underlying system delivers environmental integrity. Bridging this institutional gap is not a technical fix. It requires a structural redesign of the ICM to mirror the compliance-grade features of the EU's ETS. Imagining this substantive pivot within the Indian our bureaucratic understanding and operation anytime soon is challenging.

Shashank Pandey

is a lawyer and researcher working on environmental law and climate finance

The linking of the Carbon Border Adjustment Mechanism with the Indian carbon market is significant but there are hurdles to cross

CBAM also relies on a clear and stringent carbon price. In the EU's ETS, the price floats around €60 to €80 a tonne. In India, initial carbon credit prices hover in the range of €5 and €10. Unless the carbon price is comparable and enforced across covered sectors, European regulators will not deduct much, if anything, at the border.

Worse, exporters may end up facing both the Indian compliance cost and the EU's full CBAM levy. This creates political risk inside India, where industries may resist a "double burden" and they could lobby to water down India's scheme, i.e., compliance parameters under ICM. Bridging the price gap requires either targeted sectoral carbon contracts or a negotiated floor price that aligns with CBAM expectations. Both are politically difficult options to negotiate.

Fundamental nature of CBAM

Even if technical and price issues are solved, CBAM remains controversial. India and other developing countries have consistently opposed it at the WTO and international dialogues as being a unilateral and protectionist measure. Agreeing to a linkage between India's carbon market and CBAM, therefore, creates a political contradiction that India would be legitimising a mechanism it has formally resisted.

This tension will resurface in disputes. For instance, if the EU deems India's carbon price to be "insufficient" and refuses full deductions, exporters will cry foul, and New Delhi will be forced to escalate the issue politically or legally. There is also a sovereignty issue because carbon pricing is a domestic policy tool, but CBAM effectively gives Brussels a say in whether India's measures are "good enough". For a country that guards its policy space, this could become a red line. Beyond trade law, there is a strategic risk wherein CBAM deductions will work only if India maintains a steady, transparent carbon market. Any domestic political backtracking, for example, rolling back compliance under industry pressure, would immediately expose exporters to full CBAM costs, destabilising trade flows. In short, the linkage is hostage not only to WTO legalities but also to domestic political economy and EU-India trust.

Looking at optimistic resolutions

The Indian carbon market and CBAM linkage is one of the most significant agreements under the strategy agenda by the two big global economies. If it works, it shields Indian exporters, accelerates industrial decarbonisation, and creates a model for North-South carbon market cooperation. But weak domestic architecture, misaligned carbon prices, and political contradictions may sink it. There is an underlying case to be made for more comprehensive collaboration. India can strengthen its market design, and the EU can offer clarity and technical support for a smooth transition. Otherwise, this "breakthrough" will remain on paper, while Indian exporters continue to pay at the border.

GS. Paper 2– International Relations

UPSC Mains Practice Question: भारत के कार्बन बाज़ार और यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के बीच प्रस्तावित संबंध जलवायु शासन में उत्तर-दक्षिण सहयोग के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत करता है। भारत के लिए इस संबंध के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

Context :

- **हालिया ईयू–भारत सामरिक एजेंडा (सितंबर 2025)** वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच जलवायु सहयोग में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस साझेदारी का मुख्य आकर्षण है — **भारतीय कार्बन बाजार (ICM)** और **यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)** के बीच प्रस्तावित लिंकज (linkage)।
- सरल शब्दों में कहा जाए तो — भारतीय उत्पादक जो कार्बन मूल्य अपने घरेलू कार्बन बाजार (ICM) में चुकाएँगे, उसे यूरोपीय संघ की सीमा पर CBAM शुल्क में **घटाया जाएगा**, ताकि दोहरे कराधान (double taxation) से बचा जा सके और प्रारंभिक decarbonisation (कार्बन कटौती) के प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सके।
- हालाँकि यह कदम भारत को वैश्विक carbon pricing regime में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा अवसर है, लेकिन **संरचनात्मक, संस्थागत और राजनीतिक चुनौतियाँ** इसके सफल क्रियान्वयन में बाधा बन सकती हैं।

पृष्ठभूमि: ICM और CBAM को समझना

भारतीय कार्बन बाजार (Indian Carbon Market - ICM)

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023** के तहत शुरू किया गया।
- उद्देश्य: एक घरेलू बाजार बनाना जहाँ कार्बन उत्सर्जन allowances और credits का लेन-देन हो सके।
- लेकिन यह अभी प्रारंभिक चरण में है और अधिकतर प्रोजेक्ट आधारित है (offsets व intensity improvements) — न कि cap-and-trade मॉडल जैसा।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)

- **EU के ग्रीन डील (Green Deal)** का हिस्सा।
- यह उन आयातित वस्तुओं (इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि) पर कार्बन शुल्क लगाता है, जिनमें embedded carbon emissions अधिक हैं।
- उद्देश्य: कार्बन लीकेज रोकना — अर्थात वे उद्योग जो ढीले पर्यावरण मानकों वाले देशों में उत्पादन शिफ्ट करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. भारत का कमजोर और अधूरा कार्बन ढाँचा

- भारत का कार्बन बाजार अभी विखंडित (fragmented) है — EU के ETS (Emissions Trading System) जैसे सशक्त cap-setting, auction और verification तंत्र का अभाव है।
- वर्तमान क्रेडिट्स absolute emission caps पर आधारित नहीं हैं, जबकि EU इन्हीं को विश्वसनीय मानता है।
- **स्वतंत्र नियामक संस्था या उत्सर्जन रजिस्ट्री** की अनुपस्थिति environmental integrity को कमजोर करती है — जो EU की मान्यता के लिए अनिवार्य है।

2. मूल्य असमानता और "दोहरे बोझ" की समस्या

- **EU कार्बन मूल्य:** €60–€80 प्रति टन
- **भारतीय कार्बन मूल्य:** €5–€10 प्रति टन : यह बड़ा अंतर EU को भारतीय कार्बन लागत की पूरी कटौती स्वीकारने से रोक सकता है। परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यातकों को **दोहरा भुगतान** करना पड़ सकता है — ICM अनुपालन के लिए भी और CBAM शुल्क के रूप में भी। यह घरेलू उद्योगों में राजनीतिक असंतोष को जन्म दे सकता है।

3. राजनीतिक और संप्रभुता (Sovereignty) संबंधी चिंताएँ

- भारत पहले CBAM को WTO में "**संरक्षणवादी (protectionist) और एकतरफा (unilateral)**" कदम बताकर विरोध करता रहा है।
- अब ICM को CBAM से जोड़ना उसी नीति की वैधता स्वीकारने जैसा प्रतीत होता है।
- इससे **EU को भारत के कार्बन मूल्य निर्धारण की "पर्याप्तता" पर नियंत्रण** मिल जाता है — जो संप्रभुता के प्रश्न उठाता है।
- यदि EU भारत की मूल्य प्रणाली को "अपर्याप्त" मानकर कटौती न दे, तो भारत को कानूनी या राजनीतिक विवाद का सामना करना पड़ सकता है।

4. संस्थागत और विश्वास संकट (Institutional and Trust Deficit)

- यह लिंकज **पारस्परिक विश्वास** और **स्थिर घरेलू नीति** पर निर्भर करेगा।
- यदि भारत में किसी भी राजनीतिक दबाव के चलते अनुपालन मानक कमजोर हुए, तो निर्यातकों को पूरा CBAM शुल्क देना पड़ सकता है — जिससे व्यापारिक स्थिरता प्रभावित होगी।

महत्व और अवसर

- **दोहरे कराधान से बचाव:** भारतीय निर्यातक एक ही बार कार्बन मूल्य चुका कर प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे।
- **डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा:** उद्योगों को स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- **वैश्विक नेतृत्व:** यह उत्तर–दक्षिण सहयोग का एक मॉडल बन सकता है, जहाँ जलवायु वित्त और जिम्मेदारी में समानता हो।
- **भारत–EU संबंध सुदृढ़ होंगे:** भारत को वैश्विक जलवायु शासन (climate governance) में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करेगा।

आगे की राह (Way Forward)

1. संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- एक **स्वतंत्र उत्सर्जन नियामक प्राधिकरण (Emissions Regulatory Authority)** की स्थापना।
- Legally binding emission caps, Monitoring–Reporting–Verification (MRV) प्रणाली, और non-compliance पर दंड का प्रावधान।

2. मूल्य असमानता को कम करना

- क्षेत्र-विशिष्ट carbon contracts या floor prices विकसित करना।
- EU के साथ floor-pricing agreements पर द्विपक्षीय वार्ता करना।

3. कानूनी और कूटनीतिक स्पष्टता

- विवाद निपटान के लिए द्विपक्षीय ढाँचा तैयार करना ताकि WTO मुकदमेबाजी से बचा जा सके।
- पारदर्शी मानकों पर carbon credits की पारस्परिक मान्यता (mutual recognition) पर सहमति बनाना।

4. तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण

- EU को भारत के कार्बन बाजार के डिज़ाइन, सत्यापन और अनुपालन प्रणालियों को मज़बूत करने में **तकनीकी और वित्तीय सहयोग** देना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

- भारत के **कार्बन बाजार (ICM)** और **EU के CBAM** के बीच यह प्रस्तावित linkage उत्तर–दक्षिण सहयोग की दिशा में एक **समान और न्यायसंगत जलवायु साझेदारी (equitable climate cooperation)** का नया अध्याय खोल सकता है।
- लेकिन यदि भारत ने घरेलू स्तर पर एक विश्वसनीय, पारदर्शी और पर्याप्त मूल्य वाला कार्बन बाजार विकसित नहीं किया, तो यह साझेदारी केवल कागज़ी लाभ तक सीमित रह जाएगी जबकि उद्योगों पर वास्तविक लागत बढ़ेगी।
- इसलिए भारत को **संस्थागत सुधार, मूल्य समायोजन, और कूटनीतिक संतुलन** के साथ आगे बढ़ना होगा — ताकि यह पहल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि साझा जलवायु संघवाद (cooperative climate federalism) का वैश्विक उदाहरण बन सके।